DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 2 दिसंबर, 2023 ATED--------------------

औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान पर चुप्पी साध गए डीएसआइआइडीसी और डीडीए

उद्योग को चाहिए आधार

निहाल सिंह • नई दिल्ली

राजधानी में उद्योगों के विकास को लेकर पर सवाल पर दिल्ली विकास प्राधिकरण से लेकर दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएसआइआइडीसी) के पास में जवाब में सिर्फ खामोशी है। इनके पास यहां पर सड़कों की बदहाली से लेकर पानी और सीवरेज की समस्या को लेकर कोई जवाब नहीं है। दैनिक जागरण के सवाल पर दोनों एजेंसियों की चुप्पी बताती है कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र किस तरह अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उद्योगों के विकास और उसके संचालन के लिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में औद्योगिक क्षेत्र बनाए। इसमें 32 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र हैं जबकि 20 अनियोजित क्षेत्र हैं। डीडीए से लेकर एमसीडी, डीएसआइआइडीसी, इंडस्ट्रीज कमिश्नर जैसी प्रमुख एजेंसियों की जिम्मेदारी इन इलाकों की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करने की है। लेकिन एजेंसियों की उदासीनता से औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याएं सिर्फ कागजों में दबी रह जाती हैं। आलम यह है कि पार्किंग की समस्या के निदान का निर्णय अभी दो माह पहले ही हुआ है। अभी तक यही तय नहीं हो पा रहा था कि पार्किंग का संचालन कौन करेगा। एमसीडी करेगी या फिर डीएसआइआइडीसी। करीब दो माह पहले ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद तय हुआ है कि एमसीडी ही इन इलाकों में पार्किंग का संचालन करेगी।

वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़क • जागरण

इसी तरह इन इलाकों में साफ-सफाई से लेकर टूटी हुई सड़कों की समस्या स्थायी है, लेकिन एजेंसियां इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर डीएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक संजीव मित्तल से फोन के माध्यम से समस्याओं के समाधान को लेकर सवाल पूछा गया लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। दिल्ली सरकार ने भी इस पर मांगे जवाब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से जवाब मांगा गया लेकिन डीडीए ने भी मौन साध लिया और कोई उत्तर नहीं दिया।

सभी औद्योगिक क्षेत्रों का बना रहे हैं पार्किंग प्लान: दिल्ली नगर निगम के प्रवक्ता अमित कुमार बताते हैं कि पार्किंग की समस्या को लेकर निगम काम कर रहा है। निगम ने ओखला फेज-1, 2, 3 औद्योगिक क्षेत्रों में पार्किंग संचालन की निविदा मांगी है जबकि शेष औद्योगिक क्षेत्रों का भी प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द सभी औद्योगिक क्षेत्रों का पार्किंग एरिया प्लान बनाया जाएगा। जहां बहुमंजिला पार्किंग की जरूरत है वहां बहुमंजिला पार्किंग भी बनाने की योजना निगम की है। इसलिए पहले हम पार्किंग एरिया प्लान बना रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि सफाई के पर्याप्त साधनों का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहा है।

> दिल्ली में बड़े उद्योग अब हैं ही नहीं। जो चल रहे हैं वह लघु उद्योग हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में करीब एक लाख लघु उद्योग चल रहे हैं। इससे सीधे तौर पर 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं लेकिन समस्या यह है कि इन इलाकों से पार्षद, विधायक और सांसद को वोट नहीं मिलते हैं तो वह इन इलाकों की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि समस्याएं बहुत हैं जिन का समयबद्ध तरीके से निदान जरूरी है। दूसरे राज्यों में उद्योगों के विकास के लिए एक अलग फंड होता है, पर यहां एजेंसियों के पास इन इलाकों में विकास के लिए पर्याप्त फंड का अभाव रहता है।
>
> **- डा. अनिल गुप्ता,** अध्यक्ष, दिल्ली मैनुफैक्चरर एसोसिएशन

यमुना खादर में डीडीए ने हटाया धार्मिक ढांचा

- शास्त्री पार्क में लोहे के पुल के पास यमुना खादर में हुई कार्रवाई
- हंगामे से निपटने के लिए पुलिस बल किया गया था तैनात

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: शास्त्री पार्क में लोहे के पुल के नजदीक यमुना खादर में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को बुलडोजर की मदद से कार्रवाई करते हुए धार्मिक ढांचा हटाया। धार्मिक स्थल समिति के पदाधिकारियों के अनुसार डीडीए ने छह बुलडोजर से सुबह पांच बजे कार्रवाई करते हुए दो धार्मिक ढांचों को हटा दिया है। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का हंगामा न हो सके, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस संबंध में डीडीए से पक्ष मांगा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

यमुना खादर में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए समय-समय पर कार्रवाई करता रहता है। धार्मिक स्थल समिति के प्रधान संजीव जैन ने बताया कि यमुना खादर में धार्मिक ढांचा 30 वर्ष से था। इसमें आसपास के लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। शुक्रवार तड़के सुबह पांच बजे डीडीए ने छह बुलडोजर की मदद से इन धार्मिक ढांचों को अवैध बताकर कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई शाम पांच बजे तक चली। उनका आरोप है कि बिना किसी नोटिस या सूचना के ही डीडीए ने यह कार्रवाई कर दी है, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। धार्मिक स्थल के प्रमुख कार्यकर्ता देवनारायण मिश्रा ने बताया कि धार्मिक ढांचों को तोड़कर किसी की भावना व आस्था को ठेस पहुंचना उचित नहीं है। 30 वर्ष पुराने मंदिर को अचानक बिना किसी नोटिस या सूचना के तोड़ देने से भक्तों व मंदिर समिति के लिए उचित नहीं रहा।

लोहे के पुल के पास यमुना खादर से धार्मिक ढांचा हटने के बाद का दृश्य • सौ. सुधी पाठक

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, DECEMBER 2, 2023
NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

Oversight panel warns against Ridge violations

Priyangi.Agarwal
@timesgroup.com

New Delhi: After Delhi High Court earlier this month directed the city government to notify the Ridge as reserved forests, the oversight committee has directed Delhi Development Authority to ensure that any violation of the Forest Conservation Act does not occur on land in their possession at South-Central Ridge.

An area is declared reserved forest after it is notified under Section 20 of the Indian Forest Act (IFA). However, a preliminary notification is first made under Section 4 of the act. The tag of a reserved forest gives legal protection to Ridge and steps can be taken for conserving them better.

Delhi has the Northern Ridge, Central Ridge, South-Central Ridge and Southern Ridge and total area of these four is around 7,777 hectares.

During the recent meeting of the oversight committee, the director-general of forests and special secretary, ministry of environment, forests and climate change who heads the panel, expressed strong displeasure at the slow pace of the process of notification and directed the forest department to expedite it in a time-bound manner.

The committee said a notification under Section 20 of the IFA is to be done irrespective of the ownership of land. It was also remarked by the committee that all areas where Section 4 notification under IFA 1927 has been done,

Delhi has Northern Ridge, Central Ridge, South-Central Ridge and Southern Ridge and total area of these four ridges is around 7,777 hectares

are governed by relevant provisions of IFA 1927 and Forest (Conservation) Act 1980, and no non-forestry activity can take place in these areas without due approval.

The committee was also apprised of Forest Conservation Act violations in Mehrauli and other areas which are under ridge land and notified under the Section 4 notification of IFA. "The chairman of the committee directed that conservator of forests, Delhi, to write to all land owning agencies apprising them of the fact that giving permissions for non-forestry activity in a notified forest areas under their control is in violation of the provisions of (FCA), 1980, and in such cases they are liable for prosecution under Section 3A and 3B of FCA, 1980," the minutes of the meeting said.

As 63 institutions are on the Central Ridge, the forest department is conducting a ground survey on the actual land occupied by them following an order of the Supreme Court.

"The committee was informed that ground verification of the area occupied by the institutions and actual land use by them is being done by DCF (West)," according to minutes of meeting.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 2 दिसंबर 2023 DATED----------

यमुना खादर : 76 कॉलोनियां और धार्मिक स्ट्रक्चर हटाए जाएंगे

यमुना नदी को साफ करने की शुरू हुई कवायद

■ राम त्रिपाठी, नई दिल्ली

Surender Kumar

- 20 दिन पहले ही NGT ने खादर पर बने स्ट्रक्चर और कॉलोनियों को हटाने के तरीके बताने के लिए हाई लेवल कमिटी बनाई थी
- पहले चरण में लोहा पुल से सिग्नेचर ब्रिज तक के हिस्से में अवैध निर्माण हटाने की शुरुआत गुरुवार से हुई है

डीडीए ने शुरू की है कब्जे हटाने की कार्रवाई

यमुना को साफ करने की दिशा में नदी के खादर में बसी करीब 76 कॉलोनियों और धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। पहले चरण की योजना में लोहा पुल से सिग्नेचर ब्रिज तक के 8 किमी से अधिक के हिस्से में अवैध रूप से बने स्ट्रक्चरों को ढहाने की योजना की शुरुआत गुरुवार से हुई है।

यमुना खादर एनक्रोचमेंट रिमूवल अभियान को शुरू करने में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का दबाव माना जा रहा है। 20 दिन पहले ही एनजीटी ने खादर पर बने स्ट्रक्चर और कॉलोनियों को हटाने के तरीके बताने के लिए हाई लेवल कमिटी गठित की है। कमिटी का फोकस खादर में बसी कॉलोनियों को हटाने के उपाय खोजना है। पल्ला से वजीराबाद तक 22 किलोमीटर से अधिक लंबी नदी के खादर एरिया में अवैध रूप से बसी करीब 76 कॉलोनियों के बारे में एनजीटी को पता लगा है। इसमें बड़ी संख्या में कई धार्मिक स्थल भी हैं। एनजीटी की एक हाई लेवल कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वजीराबाद से ओखला के बीच नदी सबसे अधिक मैली हो रही है। दिल्ली में नदी में आने वाली कुल गंदगी का 76 फीसदी हिस्सा यहीं से आता है। एनजीटी इस संबंध में लोकल एजेंसियों को सख्त निर्देश भी दे रही है।

डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि एनजीटी की गतिविधियों के कारण डीडीए ने तुरंत अपनी योजना शुरू की है। इसके तहत खादर के सबसे निचले हिस्से में बनी बिल्डिंग और कच्चे ढांचों को हटाया जा रहा है। उस एरिया में बने ढांचों की पहचान हो चुकी है। उनमें धार्मिक स्थलों की संख्या अधिक है। किसी विवाद से बचने के लिए दिल्ली सरकार की रिलीजियस कम्युनिटी से भी मंजूरी ली गई है। कमिटी भी यमुना नदी को साफ रखने में सहयोग दे रही है। भारी सुरक्षा बल के साथ अभियान की कार्रवाई सुबह 5 से 7 बजे के बीच शुरू की जाएगी। सुरक्षा के लिए दिअर्धसैनिक बल भी बड़ी संख्या में तैनात रहेंगे।

लग्ज़री फ्लैट्स के लिए 24 घंटे में 460 रजिस्ट्रेशन

■ विस, नई दिल्ली: डीडीए के लग्जरी फ्लैट्स की स्कीम में महज 24 घंटे के दौरान 460 लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यह लोग रिजर्व प्राइस भरने के बाद ई-ऑक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। इस स्कीम में कुल 2,000 से अधिक फ्लैट्स उतारे गए हैं।

यह सभी फ्लैट्स पेंटहाउस, सुपर एचआईजी, एचआईजी, एमआईजी के हैं। इनमें से अधिकांश फ्लैट्स द्वारका में हैं। स्कीम के कुछ फ्लैट लोकनायकपुरम में भी शामिल हैं। डीडीए के मुताबिक फ्लैट्स की संख्या में 25 प्रतिशत लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यह रिस्पांस काफी अच्छा है। आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ सकती है।

डीडीए आवेदकों को देने के लिए पहली बार ई-ऑक्शन का रास्ता अपना रहा है। इन फ्लैट्स के लिए 29 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। डीडीए के अनुसार द्वारका सेक्टर 19बी के लग्जरी फ्लैट्स वाले गेटेड अपार्टमेंट में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। यह लोग अपनी पसंद के फ्लैट्स का बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। डीडीए पहली बार लग्जरी फ्लैट्स लोगों के लिए लेकर आया है। ऐसे में इन फ्लैट्स पर सभी की नजर है। फ्लैट्स देखने वाले आ रहे लोगों के अनुसार इनकी कीमतें काफी अधिक हैं। जगह अच्छी है इसलिए वह यहां आए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

नर्सरी : 'नेबरहुड' पर ज़ोर लेकिन दूरी 20km तक की

ट्रांसपोर्ट रूट के लिए कुछ स्कूल दे रहे हैं पॉइंट

KatyayaniUpreti@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** दूरी, सिबलिंग, अल्मनाई इन तीन खास पैमाने पर नर्सरी दाखिले की दौड़ रेस शुरू हो चुकी है। दूरी यानी घर से स्कूल की दूरी, यह क्राइटेरिया इसलिए अहम है क्योंकि शिक्षा निदेशालय का कहना है कि बच्चे का दाखिला जितने पास के स्कूल में हो उतना बेहतर। ज्यादातर स्कूलों ने डिस्टेंस/नेबरहुड को ही सबसे ज्यादा पॉइंट दिए भी है मगर कई स्कूलों ने दूरी को अपनी सहूलियत के हिसाब से रखा है। स्कूल अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस के हिसाब से बच्चों को डिस्टेंस के ज्यादा पॉइंट दे रहे हैं, चाहे स्कूल से घर की दूरी ज्यादा ही क्यों ना हो। स्कूलों ने डिस्टेंस की रेंज भी 0 से 3 या 6 किलोमीटर से खींचकर 10, 16 या 20 किलोमीटर तक भी कर दी है।

1731 में से 1595 स्कूलों ने एडमिशन क्राइटेरिया अपलोड किया

सेशन 2024-25 के लिए 1731 में से 1595 स्कूलों ने शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर एडमिशन क्राइटेरिया अपलोड कर दिया है। लगभग सभी स्कूलों ने डिस्टेंस को सबसे ज्यादा 40 से लेकर 90 पॉइंट दिए है। इस 100 पॉइंट सिस्टम में दूरी, सिबलिंग, अल्मनाई को भी स्कूलों ने प्रमुखता दी है।

लैंड डीड में पड़ोस का जिक्र: एडवोकेट और एजुकेशन एक्टिविस्ट खगेश झा कहते हैं, कई प्राइवेट स्कूलों को डीडीए की तरफ जमीन दी गई और लैंड डीड में कहा गया है कि उन्हें पड़ोस के बच्चों को दाखिला देना होगा। स्कूलों के एशेशियल सर्टिफिकेट, चाहे सरकारी जमीन में हो या प्राइवेट जमीन पर, उसमें भी पड़ोस की बात की गई है। अमूमन यह 5-6 किलोमीटर होती है। मगर कोर्ट ने स्कूलों को आसपास के इलाकों के पैरेंट्स की जरूरत के हिसाब से दूरी का दायरा बढ़ाने की इजाजत दी है मगर कोर्ट ने 12, 14 या 20 किमी तक नहीं करने को कहा है। नर्सरी यानी छोटे बच्चे, जिन्हें रोज लंबा ट्रैवल करना सही नहीं है। ट्रांसपोर्ट पर पॉइंट पहले बैन थे, मगर कोर्ट ने इसके लिए पॉइंट देने की इजाजत दे दी, जिस वजह से नेबरहुड का मतलब अब 6-7 किमी की दूरी नहीं।

दूर के इलाके कवर कर रहे हैं स्कूल: स्कूलों में डिस्टेंस की रेंज बताती है कि वे दूर के स्टूडेंट्स को भी लेना चाहते है। इसकी वजह उनकी फीस के हिसाब से इलाके को कवर करना और एनसीआर के बच्चों को खींचना भी है। बाल भवन पब्लिक स्कूल, मयूर विहार नेबरहुड के लिए 90 पॉइंट देगा। 0 से 10 किमी के लिए 90, 10 से 12 किमी के लिए 80, 12-15 के लिए 70 पॉइंट और 15 किमी से ऊपर से लिए 60 पॉइंट। प्रूडेंस स्कूल, अशोक विहार ने 55 पॉइंट तय किए है, जिसमे 10 से 15 किमी के लिए 45 पॉइंट, 15 से 20 के लिए 35 पॉइंट मिलेंगे। अनऐडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स की एक्शन कमेटी के प्रेजिडेंट भरत अरोड़ा का कहना है कि स्कूल दूरी का दायरा बढ़ाते है क्योंकि कई इलाकों में स्कूल बहुत कम है और वहां से पैरेंट्स स्कूलों से डिस्टेंस की रेंज बढ़ाने की मांग करते है। यह बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए किया जाता है।

स्कूल की गाड़ी तो एक्स्ट्रा पॉइंट: कई स्कूलों मे डिस्टेंस उसकी ट्रांसपोर्ट सर्विस के हिसाब से है। अगर स्टूडेंट दूर है मगर स्कूल की गाड़ी लेता है तो उसे ज्यादा पॉइंट मिल सकते है। जैसे टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज दूरी के लिए 50 पॉइंट तो दिए है मगर उन इलाकों के बच्चों को ये पॉइंट मिलेंगे जहां स्कूल की ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ब्लूम पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज भी 30 पॉइंट उन्हें देगा जो ट्रांसपोर्ट वाले इलाकों में रहते है। इसके अलावा, कई स्कूलों ने ट्रांसपोर्ट के 10-10 पॉइंट रखे है।

नर्सरी एडमिशन से जुड़े सवालों के हम देंगे जवाब

अगर आप भी अपने बच्चे के नर्सरी क्लास में एडमिशन को लेकर दुविधा में हैं और आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो चिंता न करें। एनबीटी आपके सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट के जरिए आप तक पहुंचाएगा।

ऐसे भेजें सवाल

nbtreader@timesgroup.com पर अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। सब्जेक्ट में लिखें NURSERY

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME O दैनिक जागरण नई दिल्ली, 3 दिसंबर, 2023

आठ सौ करोड़ से किया जाएगा गांवों का संपूर्ण विकास : एलजी

जौंती गांव से दिल्ली ग्रामोदय अभियान का किया शुभारंभ

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली : एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जौंती गांव से दिल्ली ग्रामोदय अभियान का शुभारंभ किया। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा कार्यान्वयन किए जाने वाले इस अभियान के लिए 800 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत गांवों के बुनियादी ढांचे, आजीविका, वैज्ञानिक पशुधन प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, उचित भूमि उपयोग और जल प्रबंधन को लेकर कार्य किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य उपेक्षित शहरीकृत गांवों के परिदृश्य और आजीविका में गुणात्मक परिवर्तन लाना है।

अभियान का शुभारंभ जौंती गांव में सात एकड़ के भूखंड पर दिल्ली के पहले चरागाह के काम से किया गया था। इसके अंतर्गत जौंती और आसपास के गांवों में लगभग चार हजार पशुओं को चारा प्रदान करना और क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त खुली हरी जगह प्रदान करना था। साथ ही चारागाह से सटे एक जल निकाय को भी एक सप्ताह के भीतर साफकर उसे पुनर्जीवित किया जाएगा। एलजी द्वारा चारागाह भूमि पर मोरिंगा के पौधे तथा नेपियर घास के पौधे भी लगाए। एलजी ने कहा कि चारागाह के साथ यह पहला प्रयोग यह सुनिश्चित करेगा कि सड़कों पर घूमने वाले, कूड़े के ढेर से खाने वाले और कुपोषण और दुर्घटनाओं से पीड़ित मवेशियों को उनके भरण-पोषण के लिए एक उचित पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा।

जौंती गांव में ट्रैक्टर से खेत की जुताई करते एलजी वी के सक्सेना • सौ. ट्विटर हैंडल

ट्रैक्टर से खेत जोता, अर्थमूवर पर बैठकर पेड़ की छंटाई की

इस मौके पर एलजी ने ट्रैक्टर से खेत की जुताई और अर्थमूवर पर बैठकर पेड़ों की छंटाई भी की। उन्होंने कहा कि 800 करोड़ रुपये दिल्ली में गांवों के विकास के लिए जो फंड कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, अब उसका इस्तेमाल इन गांवों के विकास के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जौंती को माडल गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा और सभी गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समान प्रयास किया जाएगा। पड़ोसी कुतुबगढ़ गांव का उदाहरण देकर बताया कि वहां कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और एक स्टेडियम पूरा होने के कगार पर है। एलजी ने कहा कि डीडीए के फंड का पूरा उपयोग दिल्ली के गांवों के संपूर्ण विकास के लिए होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 3 दिसंबर 2023 DATED----------

जौंती गांव में पशुओं के लिए 7 एकड़ में बनेगा ग्रेजिंग ग्राउंड

एलजी ने दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान की शुरुआत की

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने शनिवार को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जौंती गांव में दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान की शुरुआत की। इस परियोजना को भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत डीडीए की ओर से डिवेलप किया जाएगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस बजट को बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में, हेल्थकेयर, जमीन का सही इस्तेमाल और वॉटर मैनेजमेंट पर खर्च किया जाएगा।

जौंती ग्राउंड पर मोरिंगा और नेपियर घास के पौधे भी एलजी ने लगाए

इस पहल के साथ ही, जौंती गांव में दिल्ली के पहले ग्रेजिंग ग्राउंड के काम की शुरुआत हुई, जो 7 एकड़ भूमि पर है। यह जौंती और आसपास के गांवों में लगभग 4000 पशुओं को चारा प्रदान करने के लिए है। ग्रेजिंग ग्राउंड के पास एक जल स्रोत भी है, जिसे एक सप्ताह के भीतर साफ और गहरा कर पुनर्जीवित किया जाएगा। जौंती ग्राउंड पर मोरिंगा और नेपियर घास के पौधे भी एलजी ने लगाए थे। इस मौके पर एलजी ने कहा कि इस ग्रेजिंग ग्राउंड के साथ रास्तों पर चलने वाले पशुओं को राहत मिलेगी, जो कचरे के ढेर खाने को मजबूर हैं। सक्सेना ने यह भी निर्देश दिया कि जमीन को सही ढंग से समतल किया जाए। एलजी ने कहा कि दिल्ली में गांवों के विकास के लिए जो 800 करोड़ रुपये की निधि थी, जो पिछले वर्षों में कभी उपयोग नहीं हुई थी। वह अब इन के विकास के लिए उपयोग होगी। उन्होंने जौंती को चार मॉडल गांवों में से एक बनाने के लिए चुना है।

800 करोड़ रुपये की निधि से होंगे कई काम

NBT Lens समझिए खबरों के अंदर की बात

गांवों में विकास क्यों जरूरी?

दिल्ली में साढ़े तीन सौ से अधिक गांवों में से आधे से अधिक गांव शहरीकृत हो चुके हैं। इन गांवों में मूलभूत ढांचा विकसित न होने की वजह से बड़ी संख्या में गांवों की स्थिति स्लम से बदतर हो गई है। उधर, देहात के गांवों में आबादी बढ़ गई है, लेकिन उनके लालडोरे का मामला अटका है। स्थिति ये है कि कॉलोनियों के साथ ही गांवों में भी पानी, सीवर से लेकर सड़कें विकसित करने की जरूरत है। मसलन, अगर सीवर सिस्टम को पटरी पर नहीं लाया गया तो इससे यमुना की सफाई भी प्रभावित होगी। इसी कच्ची सड़कों से उड़ती धूल से प्रदूषण बढ़ेगा, जिसका पूरी दिल्ली पर असर पड़ेगा।

यमुना खादर में तोड़फोड़ की निंदा की

■ विस, नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि शास्त्री पार्क इलाके में यमुना खादर में प्रशासन द्वारा गोशाला को तोड़ना निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार नई गोशाला बनाने की बजाय उन्हें तोड़ रही है। लवली ने कहा कि डीडीए अपने असली काम से पीछे हट गई है। अरविन्दर सिंह लवली ने मांग की कि डीडीए तुरंत गोशाला के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, रविवार, 3 दिसंबर 2023
NEWSPAPERS---DATED---

आठ हजार से अधिक फ्लैट का पंजीकरण

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अपने 30 हजार से अधिक फ्लैट के लिए बीते 24 नवंबर से पंजीकरण शुरू किया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अब तक आठ हजार से अधिक आवेदनकर्ताओं ने फ्लैटों के लिए पंजीकरण किया है। बताया गया कि डीडीए की इस आवासीय योजना के तहत द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैटों के लिए फिलहाल पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद इन सभी फ्लैटों के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया आगामी 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगी।

उपराज्यपाल ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान जौंति गांव से शुरू किया

■ केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 800 करोड़ रुपये आवंटित किए

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को बवाना के जौंति गांव से दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की। चयनित गांवों में डीडीए की ओर से विकास कार्य कराए जाएंगे।

इस अवसर पर एलजी ने कहा कि दिल्ली ग्रामोदय अभियान शहरीकृत गांवों के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान है। केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विकास कार्यों के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस अभियान के तहत बुनियादी ढांचे, आजीविका, वैज्ञानिक पशुधन प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, उचित भूमि उपयोग और जल प्रबंधन को लेकर काम किया जाएगा। जौंति गांव में सात एकड़ के भूखंड पर दिल्ली के पहले चरागाह के निर्माण कार्य के साथ यह अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जौंती और आसपास के गांवों के लगभग 4000 पशुओं को चारा उपलब्ध कराना है। इससे सटे एक जल निकाय को भी एक सप्ताह में साफ कर उसे पुनर्जीवित किया जाएगा। एलजी ने जौंति को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए अपनाया है।

नरेला में कैंपस निर्माण प्रक्रिया तेज

नई दिल्ली, व.सं.। दिल्ली के नरेला में विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के कैंपस के निर्माण को बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर काम शुरू करने को कहा है।

डीडीए की योजना है कि नरेला में दो-तीन साल के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों के कैंपस का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अक्तूबर में डीडीए की बैठक में नरेला को एजुकेशन हब बनाने के निर्देश दिए थे। इसके मद्देनजर डीडीए की ओर से दिल्ली सरकार के इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू), गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय (डीईटीयू) के नए कैंपस को स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की जा रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
DECEMBER 3, 2023

ME OF NEWSPAPERS

Plan To Push Growth In 200 Urban Villages

Residents To Be Consulted Before Listing Work

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: To give a push to development work in urban villages, lieutenant governor VK Saxena on Saturday launched Dilli Gramodaya Abhiyan. Under the campaign, an action plan will be prepared for each village in consultation with the villagers to transform the quality of basic infrastructure, civic services, health and sports services, horticultural and water management.

The campaign will cover around 200 urban villages, including Shahpur Jat, Munirka, Ber Sarai, Pilanji, Lado Sarai, Katwaria Sarai, said an official at the LG's secretariat. Jaunti Village in North-West Delhi will be revamped first, he added.

The official further said that the campaign would be funded and implemented by Delhi Development Authority (DDA) and an amount of more than Rs 800 crore had been earmarked for it. This will be utilised for creation and upgradation of basic infrastructure, livelihoods, scientific livestock management, healthcare, proper land use and water management among others. The campaign aims at bringing about a qualitative change in the landscape and livelihood of the urbanised villages which mostly lie in neglected state, he said.

LG Saxena launches Dilli Gramodaya Abhiyan on Saturday

The campaign was launched with commencement of works for Delhi's first grazing ground in Jaunti Village on a 7-acre plot to provide fodder to nearly 4,000 livestock in Jaunti and adjoining villages as well as providing the locality with an open green space free of encroachment. A water body adjoining the grazing ground will also be cleaned, dredged, deepened and rejuvenated within a week.

The grazing ground will have a water channel on its periphery to ensure rainwater harvesting and groundwater recharge. Saplings of Moringa and nutritious grasses like Napier grass were also planted by the LG on it.

Saxena said, "This first experiment with a grazing ground in Delhi will ensure that the stray cattle moving on roads, eating from garbage dumps and suffering due to malnutrition and accidents will get a proper ecosystem for their sustenance."

The LG further said that this ground would provide healthy food to the cattle that, in turn, will also provide healthy dairy products. At the same time, it will also prevent traffic chaos and road accidents due to the presence of stray cattle on the roads. He instructed that the land should be levelled properly so that even the animals would not have any problem in reaching the grazing ground and the nearby pond.

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE SUNDAY EXPRESS, DECEMBER 3, 2023

L-G flags off campaign to develop urban villages

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, DECEMBER 2

AIMED AT developing the city's urbanised villages, L-G VK Saxena Saturday launched the 'Dilli Gramodaya Abhiyan' from Northwest Delhi's Jaunti village.

To be funded and implemented by the Delhi Development Authority, the campaign has an earmarked amount of more than Rs 800 crore which will be utilised for creation and upgradation of basic infrastructure, livelihood, scientific livestock management, healthcare, proper land use, and water management among other objectives.

L-G House officials said the campaign was launched with the commencement of work on Delhi's first grazing ground in the village on a 7-acre plot, meant to provide fodder to nearly 4,000 livestock in Jaunti and adjoining villages and provide the locality an open green space free of encroachment.

"A water body adjoining the ground will be rejuvenated in a week. The grazing ground will have a water channel on its periphery to ensure rainwater harvesting and groundwater recharge," officials said.

The L-G launched the campaign from Northwest Delhi's Jaunti village. *Express*

Saxena, who planted saplings of Moringa and grasses like Napier grass on the ground, said this "first experiment with a grazing ground in Delhi" will ensure stray cattle on roads, eating from garbage dumps and suffering due to malnutrition and accidents, get a proper ecosystem for their sustenance."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times
NEW DELHI
SUNDAY
DECEMBER 03, 2023

NAME OF NEWSPAPER

LG launches programme to revamp urbanised villages

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor (LG) VK Saxena on Saturday launched the Dilli Gramoday Abhiyaan, a targeted programme for the development and rejuvenation of urbanised villages in Delhi that will be funded and implemented by the Delhi Development Authority (DDA).

Officials from the LG's office said funds amounting to around ₹800 crore were released for this project by the Union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) earlier in October. The officials said the programme will include the upgradation of basic infrastructure, livelihoods, scientific livestock management, healthcare, proper land use, and water management for the nearly 200 urbanised villages of Delhi.

VK Saxena

The programme was launched from Jaunti village in northwest Delhi, one of the five villages adopted by the LG to be developed as "model villages". The work here commenced for Delhi's first grazing ground on a seven-acre plot meant to provide fodder to nearly 4,000 livestock in Jaunti and adjoining villages as well as providing the locality with an open green space free of encroachment. A water body adjoining the grazing ground will also be cleaned, dredged, deepened and rejuvenated within a week, officials said. The grazing ground will have a water channel on its periphery to ensure rainwater harvesting and groundwater recharge.

Speaking at the event, Saxena said, "This ground will provide healthy food to the cattle that, in turn, will also provide healthy dairy products. At the same time, it would also prevent traffic. The campaign aims to bring a qualitative change in the landscape and livelihood of the neglected villages."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 4 दिसंबर 2023

COP33 की मेज़बानी के लिए यशोभूमि है पूरी तरह तैयार

PM मोदी ने रखा है प्रस्ताव, मेज़बानी मिली तो सजेगा द्वारका

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लाइमेट चेंज सम्मेलन COP28 के दौरान COP33 के भारत में आयोजन का प्रस्ताव रखा है। COP33 का आयोजन 2028 में होना है। इससे पूर्व ही डीडीए ने G20 से भी बड़े आयोजनों के लिए यशोभूमि को भव्य बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत यशोभूमि तक जाने वाले रास्तों को उसी तरह निखारा जाएगा, जैसे G20 के दौरान एयरपोर्ट, एसपी मार्ग और भारत मंडपम के आसपास के एरिया को निखारा गया था।

यशोभूमि में P20 का सफल आयोजन हो चुका है। अब डीडीए ने मध्य दिल्ली और लुटियंस जोन के पास द्वारका में लैंडस्केपिंग और द्वारका की खूबसूरती बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। एक अधिकारी के अनुसार, यशोभूमि पर पहुंचने के लिए पालम फ्लाईओवर काफी अहम है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में पालम फ्लाईओवर से यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक के 8 किलोमीटर स्ट्रेच पर काम किया जाएगा। इसके फुटपाथ, दोनों सिरे से बनाए जाएंगे। साथ ही यहां पेड़ लगेंगे और कुछ जगहों पर फाउंटेन और स्टैच्यू भी लगाए जाएंगे। अधिकारी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट का टेंडर जल्द जारी हो जाएगा। कोशिश है कि दिसंबर के अंत तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी का नाम फाइनल कर लिया जाए।

डीडीए अधिकारी के अनुसार, अभी तक के प्लान के अनुसार द्वारका सेक्टर-1 और सात के इंटरसेक्शन पर लैंडस्केपिंग और फाउंटेन लगाने का काम होगा। इसके आसपास के अन्य सेक्टरों की पांच अलग-अलग गोल चक्करों पर मूर्तियां लगाई जाएंगी। पालम फ्लाईओवर से द्वारका की तरफ उतरते हुए यशोभूमि जाने वाले स्ट्रेच पर भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति लगाने की योजना है। हालांकि अभी इस बारे में चर्चा ही चल रही है। प्लान अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसके साथ ही द्वारका के कई हिस्सों में बिजली के खंभों को भी बदला जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी कुछ समय लग सकता है। साउथ-वेस्ट दिल्ली में पड़ने वाली द्वारका सब सिटी में इस समय करीब 10 लाख की आबादी है। यहां पर मध्यम और उच्च मध्यम परिवार अधिक रहते हैं। इसी साल अक्टूबर में एलजी वीके सक्सेना ने द्वारका और यशोभूमि का दौरा किया था।

द्वारका में लैंडस्केपिंग और द्वारका की खूबसूरती बढ़ाने का प्लान तैयार

NBT Lens समझिए खबरों के अंदर की बात — यशोभूमि पहली पसंद क्यों

यशोभूमि को इस तरह से तैयार किया गया है कि बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा के साथ मेहमानों को भी सहूलियत हो। यशोभूमि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एयरपोर्ट से महज दस किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच एरोसिटी में कई होटल भी हैं। यशोभूमि के पास द्वारका में बन रहे भारत वंदना पार्क में मेहमानों को पूरे भारत की झलक देखने को मिलेगी। यहां आयोजन होने से पूरी दिल्ली डिस्टर्ब नहीं होगी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। यशोभूमि के दूसरे चरण में होटल भी बन रहे हैं। साथ ही द्वारका में डिप्लोमेटिक एनक्लेव बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। यहां बड़े आयोजन होने से एयरपोर्ट से यहां पहुंचने के लिए लोगों को कम समय लगेगा और पूरी दिल्ली को जाम से जूझने की जरूरत नहीं होगी।

तेहखंड में 40 करोड़ से तैयार ESLF का इसी महीने हो सकता है उद्घाटन

■ विस, नई दिल्ली : तेहखंड में बनाई गई इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल साइट (ईएसएलएफ) का एमसीडी इसी महीने उद्घाटन कर सकती है। इस लैंडफिल साइट की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यहां बाकी तीन लैंडफिल की तरह कॉलोनियों से निकलने वाला कूड़ा नहीं फेंका जाएगा, बल्कि यहां ओखला स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से निकलने वाली राख को ठिकाने लगाया जाएगा। ईएसएलएफ को बनाने के लिए पूरी तरह से वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

यहां ओखला प्लांट से निकलने वाली राख को ठिकाने लगाया जाएगा

ओखला में पहले से लगभग 2000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चल रही है। लगभग इतनी ही क्षमता वाला एक प्लांट तेहखंड में तैयार किया जा रहा है। इन दोनों प्लांटों पर लगभग 4000 मीट्रिक टन कूड़ा जलने के बाद हर दिन 400 मीट्रिक टन के करीब राख निकलेगी। उसी राख को यहां ठिकाने लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि तेहखंड में डीडीए ने 47.5 एकड़ जमीन एमसीडी को दी है। इसमें से 15 एकड़ जमीन पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया गया है। बाकी बची हुई 32.5 एकड़ जमीन पर ईएसएलएफ बनाई गई है। इसे बनाने में 40 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं।

हिन्दुस्तान

संजय वन में सफाई अभियान चलेगा

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से इस माह कई बायोडायवर्सिटी पार्क में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। डीडीए और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफआई) साथ मिलकर 9 दिसंबर को संजय वन में बर्ड वॉक का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा संजय वन में सफाई अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई छात्र भी शामिल होंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

शनिवार, 2 दिसंबर 2023 NAME OF NEWSPAPERS

ई-नीलामी : पहले दिन 25% फ्लैट हुए बुक

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ई-नीलामी योजना के तहत फ्लैटों की बुकिंग कराने में लोगों ने पहले दिन खूब रुचि ली। योजना की बुकिंग शुरू होने के पहले दिन करीब 25 प्रतिशत फ्लैट बुक हो गए। लिहाजा अगले सप्ताह के अंत तक सभी फ्लैट बुक हो जाने की संभावना है।

डीडीए क अनुसार, ई-नीलामी योजना में 2093 फ्लैट शामिल किए गए हैं। इन फ्लैटों की बुकिंग की शुरुआत शुक्रवार को शुरू हुई है। पहले दिन करीब 460 फ्लैट बुक हो

गए, जबकि इन फ्लैटों की 29 दिसंबर तक बुकिंग कराई जा सकती है। इन फ्लैटों की ई-नीलामी प्रक्रिया पांच जनवरी को संपन्न होगी। ई-नीलामी में शामिल फ्लैट द्वारका सेक्टर-19बी, 14 और लोकनायकपुरम में उपलब्ध हैं। इस चरण में शामिल पेंटहाउस की आरक्षित कीमत पांच करोड़ लाख रुपये रखी है, वहीं सुपर एचआईजी फ्लैटों की कीमत ढाई करोड़ रुपये आरक्षित की गई है। इस योजना में 14 पेंटहाउस शामिल हैं और यह सभी द्वारका सेक्टर-19बी फेज-2 में उपलब्ध हैं, जबकि इसी जगह 170 सुपर एचआईजी और 946 एचआईजी फ्लैट उपलब्ध हैं, वहीं एमआईजी फ्लैट द्वारका सेक्टर-14 में 316 और 647 एमआईजी फ्लैट लोकनायकपुरम में उपलब्ध हैं। ब्यूरो

पंजाब केसरी

डीडीए प्रीमियम आवासीय योजना के लिए 460 पंजीकरण

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की प्रीमियम आवासीय योजना के तहत 24 घंटे में ही 460 से अधिक पंजीकरण हो गए हैं। यह संख्या इस योजना के लगभग दो हजार लग्जरी फ्लैटों की लगभग 25 प्रतिशत है। ज्ञात हो कि सभी फ्लैट ई-नीलामी के जरिये आवंटित किए जाएंगे। योजना में द्वारका सेक्टर-19 बी के बने डीडीए कांप्लेक्स में 14 पेंटहाउस, 170 सुपर एचआइजी और 946 एचआइजी फ्लैट शामिल हैं। इसके अलावा इसी योजना में द्वारका सेक्टर-14 में बने 316 एमआइजी और लोकनायक पुरम में बने 647 एमआइजी फ्लैट्स भी शामिल हैं। फ्लैटों के लिए पहली बार होने जा रही इस नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लोगों को ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपाजिट) के तहत 10 लाख से 25 लाख रुपये भी जमा करवाने होंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। रविवार • 3 दिसम्बर • 2023 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

दिल्ली ग्रामोदय अभियान से बदलेगा गांवों का बुनियादी ढांचा

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के गांवों के बुनियादी विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित दिल्ली ग्रामोदय अभियान का शुभारंभ शनिवार को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जौंती गांव से किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से गांवों के बुनियादी ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन दिखेगा।

दिल्ली के गांवों का विकास भी अन्य इलाकों के तर्ज पर ही किया जाएगा। इस अभियान के लिए डीडीए से करीब 800 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, जो गांवों के विकास पर ही खर्च किया जाएगा। इस फंड से पशुधन प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, भूमि का समुचित इस्तेमाल एवं जल प्रबंध पर किया जाएगा। उप-राज्यपाल ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पांच गांव कुतुबगढ़, निजामपुर, राबता, देवराला और जौंती गांव को गोद ले रखा है।

उप-राज्यपाल ने बताया कि अभियान का उद्देश्य उपेक्षित शहरीकृत गांवों के परिदृश्य और आजीविका में गुणात्मक सुधार लाना है। जौंती गांव में 7 एकड़ जमीन

पर एक चारागाह बनाया गया है। इससे करीब 4000 पशुओं को हरा चारा मिलेगा। चारागाह से हरियाली बढ़ेगी और आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। चारागाह से सटे एक तालाब बनाने की भी पहल की गई है। सप्ताहभर में यह तालाब बनकर तैयार हो जाएगा।

उप-राज्यपाल ने बताया कि चारागाह की परिधि में एक वाटर चैनल भी विकसित किया जाएगा। इसमें बरसाती पानी एकत्र कर भूजल स्तर को ऊपर लाने काम किया जाएगा। चारागाह की भूमि पर मोरिंगा के पौधे लगाकर नेपियर जैसी घास की रोपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यह अपने तरह का पहला प्रयोग है। इससे आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। चारागाह में दूध देने वाले पशुओं का दूध मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उप-राज्यपाल ने ट्रैक्टर चलाया और जेसीबी से पेड़ों की छंटाई भी की। कुतुबगढ़ गांव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गावों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विकास योजनाएं शुरू

- एलजी वीके सक्सेना ने जौंती गांव में किया शुभारंभ
- डीडीए से मिले 800 करोड़ के फंड से गावों का होगा विकास
- जौंती गांव में 7 एकड़ पर बनेगा चारागाह, पशुओं को मिलेगा चारा

की गई हैं। एक स्टेडियम का कार्य अंतिम चरण में है। इससे पहले उप-राज्यपाल 3 अक्टूबर को जौंती गांव गए थे।

उन्होंने बताया कि जौंती गांव के लिए कई विकास योजनाएं पाइपलाइन में हैं। उप-राज्यपाल ने कहा कि पहलवानों की प्रतिस्पर्धा ने लोगों का दिल जीतने का काम किया है। कुतबगढ़ गांव में डीडीए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसमें सभी बुनियादी खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी तर्ज पर अन्य गावों का भी विकास किया जाएगा।

कड़ाके की ठंड में गौशाला तोड़ना अपराध

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि शास्त्री पार्क क्षेत्र यमुना खादर में प्रशासन द्वारा गौशाला को तोड़ना निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केन्द्र सरकार के अधीन डीडीए द्वारा कड़कती ठंड में गौशाला को तोड़ना अपराध है। भाजपा सरकार नई गौशाला बनाने की बजाय उन्हें तोड़ रही है। यह लोगों की धार्मिक आस्था के प्रति अपमान है, क्योंकि लोग गाय की पूजा करते हैं। डीडीए अपने असली काम से पीछे हट गई है। लवली ने तोड़ी गई गऊशाला का जायजा लेने के लिए कांग्रेस टीम को भेजा था। इसमें पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता, जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज, रमाकांत गोस्वामी, हरी किशन जिंदल, कमलकांत शर्मा, हरनाम सिंह, अनुज आत्रेय, मोहम्मद उस्मान, सुखबीर शर्मा, एसके पुरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे।

नई गौशाला बनाने की बजाय प्रशासन का उन्हें तोड़ना लोगों की धार्मिक आस्था का अपमान : लवली

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने मांग की कि डीडीए तुरंत उजाड़ी गई गौशाला के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करे। जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होती, प्रशासन गौशाला के लिए अस्थायी व्यवस्था करे। इस पूरे मामले में भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की आक्रामक कार्रवाई में एक गाय की मृत्यु होना अत्यंत दुखद है।

गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने खादर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर कांग्रेस की टीम को भेजा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यहां गौशाला और रहने वाले लोगों को उजाड़ दिया है तथा अन्य नजदीक रह रहे और लोगों को उजाड़ने की तैयारी सरकार कर रही है। डीडीए की कार्रवाई से यहां भारी नुकसान हुआ है और गौशाला को बुलडोजर और भारी पुलिस द्वारा बेरहमी से तोड़े जाने पर लोगों में भारी रोष व्याप्त है तथा यहां प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करने पर भी लोगों में भारी गुस्सा है।

लवली ने कहा कि राजधानी में आज हजारों गाय आवारा घूम रही हैं, जिन्हें चारा देने वाला कोई नहीं है। दिल्ली नगर निगम, डीडीए और प्रशासन इन गायों के रखरखाव में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने मांग की कि आवारा घूम रही गायों के लिए सरकारी गौशाला बनाई जानी चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE HINDU Sunday, December 3, 2023 DELHI DATED----------

Saxena launches ₹800-crore campaign for urban villages

Under the 'Dilli Gramodaya Abhiyan', 135 villages in the Capital to get access to better health, civic, and sports facilities; as part of the programme, L-G inaugurates 7-acre grazing land for stray cattle

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Lieutenant-Governor V.K. Saxena on Saturday launched an ₹800-crore campaign, 'Dilli Gramodaya Abhiyan', to develop urban villages in the national capital.

A Raj Niwas official said the campaign, funded and implemented by the Delhi Development Authority, will ensure that all 135 urban villages in Delhi get an infrastructure boost, landscape upgrade, and civic services on a par with the more developed parts of the city.

Announcing the programme in north-west Delhi's Jaunti village, Mr. Saxena inaugurated a seven-acre plot to provide fodder to nearly 4,000 livestock. A waterbody adjoining the grazing ground will also be cleaned, dredged, deepened, and rejuvenated within a week, said officials. It will have a water channel on its periphery to ensure rainwater harvesting and groundwater recharge.

The initiative will be executed by the Delhi Development Authority, L-G V.K. Saxena (left) said on Saturday. SPECIAL ARRANGEMENT

'First of its kind'

The L-G said the seven-acre field is a first of its kind experiment in the Capital, which will ensure that stray cattle on the roads, often seen consuming garbage and being hit by passing vehicles, get a proper ecosystem for their sustenance.

A Raj Niwas official said under the 'Dilli Gramodaya Abhiyan', an action plan will be prepared for each village in consultation with the residents to transform the basic infrastructure, including civic services, health, and sports facilities, in addition to which horticultural upgrades and water management resources will also be provided.

Earlier this year, the L-G had adopted five villages in north-west Delhi – Jaunti, Qutabgarh, Nizampur, Rawta, and Deorala – to be developed as self-sustainable model villages.

A Raj Niwas official said the Qutabgarh village, adopted in February, has already seen a lot of development in several sectors.

"The waterbodies in the area have been rejuvenated, community centres created, water pipelines mended, and parks renovated," the official said.

"Moreover, a sports complex is also being built, which will have facilities for various sports, including cricket, badminton, and wrestling. The work on it is expected to be completed in a month," the official said, adding that the other villages have also seen similar development.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
SUNDAY, 3 DECEMBER, 2023 | NEW DELHI

DATED

Delhi L-G launches campaign for development of urbanised villages

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lieutenant Governor V K Saxena launched the "Dilli Gramodaya Abhiyan" on Saturday for the development of urbanised villages in the national capital with a dedicated fund of more than Rs 800 crore.

Under the ambitious campaign funded and conducted by the Delhi Development Authority (DDA), the urbanised villages in the capital will get major infrastructure boost, landscape upgrade and civic services at par with the main city, according to a statement issued by the Raj Niwas.

Launching the campaign from Jaunti village, Saxena said the Rs 800-crore fund for village development was never utilised and it has now been transferred to the DDA, following the transfer of gram sabha land according to the extant regulations and policy decisions.

Implemented by the DDA that functions under the Ministry of Housing and Urban Affairs, the campaign fund will be utilised for creating and upgrading basic infrastructure, livelihoods, scientific livestock management, healthcare, proper land use and water management. An action plan will be prepared for each village in consultation with the villagers to transform the quality of basic infrastructure, civic services, health and sports services, horticultural upgrade and water management, the statement said.

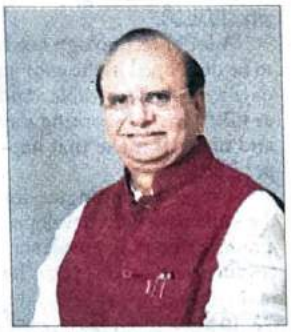

L-G VK Saxena

Under the campaign, Delhi's first grazing ground will be developed in Jaunti, on a seven-acre plot meant to provide fodder to nearly 4,000 livestock, besides preparing an open green space free of encroachment in the area, the statement said.

A water body adjoining the grazing ground will also be cleaned, dredged, deepened and rejuvenated within a week.

The grazing ground will have a water channel on its periphery to ensure rainwater harvesting and groundwater recharge.

Saplings of moringa and nutritious grasses like the Napier grass were also planted by the L-G on the grazing ground.

Saxena said the grazing ground will ensure that the stray cattle moving on roads, eating from garbage dumps and suffering due to malnutrition and accidents will get a proper ecosystem for their sustenance.

After launching the campaign, the L-G also drove a tractor, ploughed a stretch of land and steered a backhoe machine.

He said efforts would be undertaken to make all the villages self-sustainable.

रविवार
03.12.2023
dainikbhaskar.com

एलजी ने गांवों के विकास के लिए अभियान शुरू किया

नई दिल्ली | एलजी वीके सक्सेना ने 800 करोड़ रुपए की समर्पित निधि से दिल्ली के शहरीकृत गांवों के विकास के लिए 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' शुरू किया। राजनिवास के बयान के अनुसार, डीडीए के इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत शहरीकृत गांवों को मुख्य शहर की भांति बुनियादी ढांचे मिलेंगे, उनका कायाकल्प होगा और उन्हें नागरिक सेवाएं मिलेंगी। डीडीए इसका वित्तपोषण भी करेगा। जौंती गांव से इस अभियान की शुरुआत करते हुए एलजी ने कहा कि ग्राम विकास के लिए 800 करोड़ रुपए की निधि का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

sunday pioneer
NEW DELHI | SUNDAY | DECEMBER 3, 2023
DATED

LG launches 'Dilli Gramodaya Abhiyan' for urbanised villages

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor(LG) Vinai Kumar Saxena on Saturday here launched the "Dilli Gramodaya Abhiyan' an ambitious campaign for the development of urbanised villages of the Capital, from Jaunti Village in North-West Delhi. The campaign has an earmarked amount of more than Rs 800 crores.

Giving details here, officials the campaign will be funded and implemented by the Delhi Development Authority (DDA), under the Ministry of Housing and Urban Affairs.

The funds will be utilized for creation and up gradation of basic infrastructure, livelihoods, scientific livestock management, healthcare, proper land use and water management among others. The campaign aims at bringng about a qualitative change n the landscape and livelihood of the hitherto neglected, urbanized villages in the city.

The campaign was launched with commencement of works for Delhi's first grazing ground in Jaunti Village, on a 7-acre plot meant to provide fodder to nearly 4000 livestock in Jaunti and adjoining villages as well as providing the locality with an open green space free of encroachment.

A water body adjoining the grazing ground will also be cleaned, dredged, deepened and rejuvenated within a week. The grazing ground will have a water channel on its periphery to ensure rainwater harvesting and groundwater recharge. Saplings of Moringa and nutritious grasses like Napier grass were also planted by the LG on the grazing ground.

Speaking on the occasion, Saxena said this first experiment with a grazing ground in the Capital will ensure that the stray cattle moving on roads, eating from garbage dumps and suffering due to malnutrition and accidents will get a proper eco system for their sustenance.

He said this ground will provide healthy food to the cattle that, in turn, will also provide healthy dairy products. At the same time, it would also prevent traffic chaos and road accidents due to presence of stray cattle on the roads.

Saxena instructed that the land should be levelled properly so that even the animals would not have any problem in reaching to the grazing ground and the nearby pond.

Launching the program, the LG sat on steering of a tractor and ploughed a stretch of land and also sat on a JCB vehicle guiding, the workmen in pruning the trees and clearing the waste.

Saxena said the Rs. 800 Cr. fund for village development in Delhi, which was never utilized in the past years, will now be used for development of these villages. The fund has been transferred to the DDA, following the transfer of Gram Sabha Land as per extant regulations and policy decisions.

Saxena, who has adopted Jaunti as one of the four villages for developing as model villages said that same effort would be made to make all villages self-sustainable and gave the example of neighbouring Qutabgarh Village, where lot of infrastructure development projects are being undertaken and a stadium is on the verge of completion.

The LG recalled that after his visit on October 3, to the Jaunti Village, lot of initiatives have been taken during the last 02 months and more works were in the pipeline. He appreciated that youngsters particularly wrestlers, who have shown promising achievements by winning accolades in various championships.

The LG said the funds from the DDA should be utilized fully for the overall development of the villages in the National Capital. Special emphasis will be given on healthcare facilities.

Under the 'Dilli Gramodaya Abhiyan,' urbanized villages will be provided with essential amenities to improve the living conditions in these villages. Under this Campaign, an Action Plan will be prepared for each village in consultation with the villagers to transform the quality of basic infrastructure, civic services, health and sports services, horticultural upgrade and water management.

It may be noted that earlier the LG had undertaken the development of 05 villages as model villages in the North-West Delhi, namely Qutabgarh, Nizampur, Rawta, Deorala and Jaunti.

Qutabgarh village was adopted as a model village in February, 2023 and in the last 10 months, the village has seen development in all sectors. The developments include rejuvenation of waterbodies, renovation of parks, community centres/PanchayatGhars, repair of DJB pipelines, upgradation of MCD dispensary to polyclinic, creation of model Anganwadi, implementation of government schemes through special camps etc.

A sports complex is also being built in Qutabgarh by the DDA and will have facilities for cricket, badminton, volley ball, wrestling etc. The stadium is expected to be completed in a month.

On receiving positive response from the villagers on the ongoing development works in Qutabgarh, a similar model village development plan was also initiated for NizampurRashidpur and Jaunti in July, 2023.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला
नई दिल्ली | रविवार, 3 दिसंबर 2023
NAME OF NEWSPAPERS-----DATED-----

800 करोड़ से मॉडल बनेंगे शहरीकृत गांव

उपराज्यपाल ने जौंती गांव से शुरू किया दिल्ली ग्रामोदय अभियान, 175 शहरीकृत गांव हैं राजधानी में

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली के शहरीकृत गांव मॉडल बनेंगे। इन गांवों में 800 करोड़ से बुनियादी ढांचे का सुधार किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की वित्त पोषित दिल्ली ग्रामोदय अभियान को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जौंती गांव में लॉन्च किया।

इस अभियान में दिल्ली के सभी शहरीकृत गांव को अपग्रेड किया जाएगा। यहां पर रहने वाले लोगों को मुख्य शहर की तरह बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि दिल्ली में करीब 175 शहरीकृत गांव हैं। इस अभियान के बारे में अधिकारियों ने बताया कि यह केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। इसके तहत डीडीए 800 करोड़ रुपये से अधिक के फंड से सभी गांव का विकास करेगा।

गांव में बुनियादी ढांचे, आजीविका, वैज्ञानिक पशुधन प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, उचित भूमि उपयोग, जल प्रबंधन सहित अन्य के लिए काम किया जाएगा। इससे इन गांव में रहने वाले लोगों के आजीविका में गुणात्मक सुधार होगा। अभी तक यह गांव उपेक्षित थे। इस अभियान के तहत जौंती गांव के सात एकड़ भूखंड पर दिल्ली का पहला चरागाह बनेगा। शनिवार को इस चरागाह बनाने की शुरूआत एलजी ने की। इस चरागाह की मदद से जौंती और आसपास के गांवों के करीब चार हजार पशुओं को चारा मिलेगा।

साथ ही आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटेगा व हरियाली बढ़ेगी। इस चारागाह से सटे एक जल निकाय को भी विकसित किया जा रहा है। अगले एक सप्ताह में इसे पूरी तरह से साफ किया जाएगा। साथ ही इसे खोदकर इसकी गहराई बढ़ाई जाएगी। इसे पुनर्जीवित किया जाएगा। इसकी मदद से वर्षा जल संचयन कर भूजल स्तर को सुधारा जाएगा। शनिवार को एलजी ने चारागाह भूमि पर मोरिंगा के पौधे तथा नेपियर घास भी लगाया।

अभियान की शुरुआत पर पौधरोपण करते लोग। स्रोत: राजनिवास

07
एकड़ में बनेगा पहला चारागाह

4000
पशुओं को मिलेगी सुविधा

लावारिस पशुओं की समस्या होगी दूर

एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में पहली बार कोई चरागाह बनाकर प्रयोग किया जा रहा है। इसकी मदद से सड़कों पर घूमने वाले लावारिस मवेशियों की समस्या दूर होगी। साथ ही इन पशुओं को पर्याप्त भरण-पोषण मिलेगा। इन्हें कूड़े का ढेर खाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इनके कुपोषण व दुर्घटनाओं को दूर कर मवेशियों की जिंदगी में सुधार लाया जाएगा। एलजी ने कहा कि यह मैदान मवेशियों को स्वस्थ भोजन प्रदान करेगा। जो बदले में स्वस्थ डेयरी उत्पाद भी प्रदान करेगा। साथ ही सड़कों पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकेगा।

तालाब तक बनाया जाएगा रास्ता

एलजी ने निर्देश दिया कि चरागाह पर जमीन को ठीक से समतल किया जाए ताकि जानवरों आसानी से तालाब तक पहुंच पाए। इस दौरान उपराज्यपाल ने ट्रैक्टर पर बैठकर जमीन की जुताई भी की। साथ ही जेसीबी पर बैठकर पेड़ों की छंटाई और कचरे को साफ करने में श्रमिकों की मदद की।

कई सालों से फंड का नहीं हो पाता था इस्तेमाल

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि 800 करोड़ रुपये के फंड का पिछले कई सालों में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसका इस्तेमाल इन गांवों के विकास के लिए किया जाएगा। मौजूदा नियमों और नीतिगत निर्णयों से ग्राम सभा भूमि के हस्तांतरण के बाद धनराशि डीडीए को हस्तांतरित कर दी गई है। बता दें कि जौंती गोद लिए गए चार गांवों में से एक है। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समान प्रयास किया जा रहा है। कुतुबगढ़ गांव में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है जो जल्द ही पूरा होने वाला है। एलजी ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली में पांच गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने का काम करवाया है। ये गांव कुतुबगढ़, निजामपुर, रावता, देवराला और जौंती हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI ▸ 3 दिसम्बर, 2023 ▸ रविवार

ग्रामोदय अभियान जौंती गांव से एलजी ने की दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत, इन्फ्रास्ट्रक्चर,स्वास्थ्य सुविधाओं और लोगों की आजीविका में होगा सुधार

800 करोड़ से बदलेगी शहरीकृत गांवों की सूरत

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जौंती गांव से राजधानी के शहरीकृत गांवों के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' की शुरुआत की। इससे दिल्ली के शहरीकृत गांवों की सूरत बदलेगी। केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत डीडीए द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित किए जाने वाले इस अभियान के लिए 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की गई है, इससे गांवों के बुनियादी ढांचे, आजीविका, पशुधन प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, भूमि का उचित उपयोग और जल प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य अब तक उपेक्षित रहने वाले शहरीकृत गांवों के परिदृश्य और आजीविका में गुणात्मक परिवर्तन लाना है।

प्रत्येक गांव के लिए अलग से तैयार की जाएगी कार्य योजना

इस दौरान एलजी ने कहा कि दिल्ली में गांव के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये के फंड का पिछले कई वर्षों में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, अब यह धनराशि डीडीए को हस्तांतरित कर दी गई है जिसका इस्तेमाल इन गांवों के विकास के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीडीए के फंड का पूरा उपयोग दिल्ली के गांवों के समग्र विकास के लिए किया जाएगा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कुतुबगढ़ गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से वहां पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई विकास योजनाएं शुरू की गई हैं और एक स्टेडियम का काम पूरा होने के करीब है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत राजधानी के शहरीकृत गांवों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस अभियान के तहत ग्रामीणों से वहां के बुनियादी ढांचे, नागरिक सेवाओं, स्वास्थ्य और खेल सेवाओं, बागवानी और जल प्रबंधन की गुणवत्ता में बदलाव के लिए परामर्श कर प्रत्येक गांव के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले एलजी ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली में 5 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का काम किया था, जिनके नाम कुतुबगढ़, निजामपुर, रावता, देवराला और जौंती हैं।

'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के दौरान दिल्ली के जौंती गांव में ट्रैक्टर चलाते एलजी वीके सक्सेना।

सात एकड में बनेगा दिल्ली का पहला चारागाह

एलजी ने कहा कि जौंती गांव में 7 एकड़ जमीन पर दिल्ली के पहले चारागाह के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इससे जौंती और इसके आसपास के गांवों में लगभग 4000 पशुओं को चारा मिलेगा। चारागाह के करीब स्थित एक तालाब को एक सप्ताह के अंदर साफ कर पुनर्जीवित किया जाएगा। इस दौरान एलजी ने कहा कि राजधानी में चारागाह को लेकर किया गया यह दिल्ली में पहला प्रयोग है, जिससे सड़कों पर घूमने वाले व कूड़े के ढेर से खाने वाले आवारा पशुओं का भरण-पोषण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह मैदान पशुओं को पौष्टिक भोजन देगा और बदले में स्वस्थ डेयरी उत्पाद भी मिल सकेंगे। इसके साथ ही सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली अव्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकेगा।

हाउसिंग स्कीम के लिए डीडीए ने लगाया हेल्पडेस्क

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी फेस्टिवल धमाका हाउसिंग स्कीम 2023 से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विकास सदन स्थित डीडीए मुख्यालय में एक हेल्पडेस्क स्थापित किया है। इस हेल्पडेस्क पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच योजना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान यहां मौजूद कर्मचारी इच्छुक लोगों को योजना की जानकारी देंगे और उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- पंजाब केसरी ▶ 3 दिसम्बर, 2023 -ED----------

डीडीए गोशाला के लिए वैकल्पिक स्थान दे: कांग्रेस

नईदिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि शास्त्री पार्क क्षेत्र यमुना खादर में प्रशासन द्वारा गौशाला को तोड़ना निदंनीय है। भाजपा सरकार नई गौशाला बनाने की बजाय उन्हें तोड़ रही है यह लोगों की धार्मिक आस्था के प्रति अपमान है, क्योंकि लोग गाय की पूजा करते है।

लवली ने हमला बोलते हुए कहा कि डीडीए अपने असली काम से पीछे हट गई है। गौरतलब है कि लवली ने खादर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर कांग्रेस की टीम को भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता, जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज, पूर्व जिलाध्यक्ष हरी किशन जिंदल, मो. उस्मान के अलावा हरनाम सिंह, अनुज आत्रेय आदि शामिल थे। उन्होंने बताया कि गौशाला को बुलडोजर और भारी पुलिस द्वारा बेरहमी से तोड़े जाने पर लोगों में भारी रोष व्याप्त है तथा यहां प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करने पर भी लोगों में भारी गुस्सा है। कांग्रेस ने वैकल्पिक स्थान की मांग की है।

गोशाला तोड़ने पर जताया विरोध

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): यूनाइटिड हिन्दू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा नेता जय भगवान गोयल ने कहा कि शनिवार को सभी गो भक्त एकत्रित होकर सभी गोवंश को साथ लेकर उपराज्यपाल निवास जाना चाहते थे, ताकि इन सभी गोवंशो की भविष्य में उचित व्यवस्था, उपराज्यपाल कराएं या गोशाला को पुनः सरकारी खर्चे पर निर्माण कराए ताकि आने वाले दिनों में भारी सर्दी होने पर ओर ज्यादा गोवंशों की मृत्यु न हो सक, लेकिन भारी भरकम पुलिस बल द्वारा जबरदस्ती वहां जाने पर उन्हें रोका गया। गोयल ने आरोप लगाया कि डीडीए द्वारा आईएसबीटी यमुना पुल के पास व श्यामगिरी मठ के पीछे निर्दयता से बिना कोई पूर्व सूचना दिए वर्षों पुरानी गोशाला तहस-नहस किए जाने पर गोभक्तों में भारी रोष है। इसी तोड़-फोड़ के दौरान एक गो माता की मृत्यु भी हो गई। उन्होंने बताया कि इस गोशाला में लगभग 500 गाय, बछड़े, नन्दी, बीमार गाय, बछिया, गोवंश की सेवा आसपास के गोभक्तों द्वारा मिलकर की जा रही थी। तोड़फोड़ व गोमाता की मृत्यु से गो प्रेमियो को भारी आघात लगा है। गोयल ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द 500 गोवंश की उचित व्यवस्था कराएं और अवैध रूप से तोड़ी गई गोशाला का निर्माण कराएं अन्यथा, 5 दिसम्बर को सभी गोभक्त, सन्तों के मार्गदर्शन में एलजी हाउस का घेराव करेंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

4 दिसम्बर • 2023 | राष्ट्रीय सहारा PAPERS----------DATED----------

सभी गांवों का हाउस टैक्स एक साथ करें माफ

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

दिल्ली पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने मेयर शैली ओबराय से दिल्ली देहात व ग्रामीण व शहरीकृत गांवों के हाउस टैक्स पर उनकी घोषणा पर स्पष्टता की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेयर ने सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के गांवों की रिहायशी क्षेत्र पर हाउस टैक्स माफ करने की बात की है। दिल्ली के 360 गांव व उनकी पंचायतें एक हैं, इन्हें बांटने का काम न करें। सभी गांवों के हाउस टैक्स माफ एक साथ करें।

■ दिल्ली पंचायत संघ प्रमुख ने कहा गांवों पर बेबुनियाद थोपे नियम व कानूनों का विरोध होता रहेगा, गांवों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार बर्दाश्त नहीं

■ हाउस टैक्स माफ की घोषणा दिल्ली नगर निगम के किस एक्ट व नियम के तहत हुई है, बताएं मेयर

थान सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली पंचायत संघ की लगातार पिछले दो वर्षों से दिल्ली के सभी गांवों का हाउस टैक्स माफ, आवासीय व व्यावसायिक दोनों श्रेणी का, गांवों को भवन उपनियम से बाहर करें, गांवों को व्यावसायिक श्रेणी में करें तथा गांवों की सील संपत्ति खोलने की मांग करता आ रहा है। समय-समय पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा हाउस टैक्स माफ की घोषणा की जाती रही है, लेकिन कोई इस पर काम नहीं होता। सिर्फ गांव वाले गुमराह हो रहे हैं। पंचायत संघ की मांग है कि दिल्ली नगर निगम नोटिफाइड सड़कों का दोबारा से सर्वे करे और डीडीए द्वारा आवासीय सोसाइटीज व आवासीय संपत्तियों की सड़कों को इससे बाहर करे। मास्टर प्लान के तहत गांवों की कृषि भूमि अधिग्रहीत की थी इसलिए इन्हें व्यावसायिक श्रेणी में नहीं किया जाए। गांवों पर बेबुनियाद थोपे नियम व कानूनों का विरोध होता रहेगा और गांवों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि मेयर जल्द स्पष्ट करें, नहीं तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश के पैतृक गांव शकूरपुर में महापंचायत बुलाई जाएगी और दिल्ली देहात ग्रामीण व शहरीकृत गांवों के हाउस टैक्स माफी और 18 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर निर्णय लिया जाएगा। पूर्व परिवहन एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह शौकीन व पूर्व विधायक विजय लोचव ने कहा कि हाउस टैक्स माफ की घोषणा दिल्ली नगर निगम के किस एक्ट व नियम के तहत हुई है। क्या शहरीकृत व ग्रामीण गांवों की सभी आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों से हाऊस टैक्स नहीं लिया जाएगा, इस बाबत मेयर स्पष्ट करें।